to prescribe coercive and intrusive suggestions which could be counterproductive.

बेलारूस के शासनाध्यक्ष की भारत यात्रा

2496. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेलारूस के शासनाध्यक्ष ने हाल में ही भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कोई समझौते किए गए;

(घ) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) क्या उन्होंने भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार-संबंधी और संयुक्त उद्यम लगाने के लिए पेशकश की और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) बेलारूस गणराज्य के राष्ट्रपति ने 25—28 सितम्बर 1997 को भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों सहित आपसी हित के सभी मसलों को शामिल किया गया। इनसे एक दूसरे की हित-चिन्ताओं के प्रति समझबूझ में वृद्धि हुई और विविध क्षेत्रों में बेलारूस के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ हुए।

(ग) और (घ) इस यात्रा के दौरान भारत और बेलारूस के बीच पांच द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए. इसकी प्रमुख बातें हैं:—

I. दोहरे कराधान के परिहार से संबद्ध करार:

इस करार में दोनों देशों में व्यक्तियों और कार्पोरेट निकायों की आय पर एक से अथवा काफी हद तक एक जैसे, करों से बचने का प्रयास है। इससे दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा आपसी निवेश संवर्धित होगा तथा एक दूसरे के क्षेत्र में अपनी वास्तविक मौजूदगी के द्वारा निवेशकर्ताओं फर्मों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

II. डाक और दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार:

इस करार से दोनों देशों के संचार प्राधिकारियों के बीच संयोगात्मक ढांचा तैयार करके भारत और बेलारूस तथा अन्यत्र डाक और दूरसंचार सेवाओं को सुधारने में मदद मिलेगी। इससे आपसी लाभ के लिए विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारी का द्विपक्षीय आदन-प्रदान भी बढ़ेगा।

III. आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अंतर-सरकारी आयोग के गठन से संबद्ध करार:

इस करार के द्वारा, द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक मामलों पर बातचीत के लिए एक अन्तर-सरकारी आयोग का गठन किया गया है।

IV. हाई सेवा से संबद्ध करार:

यह करार दोनों देशों में दिल्ली और मिंस्क और भारत और बेलारूस के एक-एक शहर के बीच निर्धारित एअर लाइंसों की निर्धारित उड़ानों के प्रचालन के लिए ढांचा तैयार करता है। ऐसी उड़ानें द्विपक्षीय व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देंगी।

V. विदेश कार्यालय परामर्श संबंधी प्रोतोकोल:

इस प्रोतोकोल में आपसी हितचिन्ताओं के सभी मसलों पर भारत के विदेश मंत्रालय और बेलारूस के विदेश मंत्रालय के बीच द्विवार्षिक परामर्शों का प्रावधान है।

(ङ) यात्रा के दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति ने भारत-बेलारूस व्यापार और आर्थिक सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने में रूचि ली। भारतीय पक्ष ने ऐसी ही इच्छा प्रकट की। बेलारूस के विदेश आर्थिक संबंध मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन तथा मुम्बई में भारत-बेलारूस ट्रेडिंग हाउस खोलने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

U.S. Aid Package to Pakistan

2497. **SHRIMATI VEENA VERMA:**
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the PRIME MINISTER of be pleased to state:

(a) whether the U.S. had offered a massive aid package to Pakistan as an

inducement to deter Islamabad from conducting nuclear tests;;

(b) if so, the details of the package; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) and (b)
there were media reports that in order to dissuade Pakistan from conducting nuclear tests, the US may offer to Pakistan military and economic aid. Such assistance is presently restricted under US domestic laws, namely the Pressler Amendment.

(c) Pakistan has since conducted nuclear tests, and the US has imposed sanctions in addition to those already in place under the Pressler Amendment.

U.S. President's Statement on Nuclear Weapons

2498. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the US-President made on the eve of the P-5 meet of the Security Council held in first week of May, 1998;

(b) whether in this statement the US-President referred to the progress made over the past years in reducing stock piles and containing the spread of nuclear weapons and if so, the details of the progress made in this direction as referred to by US President; and

(c) what is Government's reaction thereto by way of taking steps for improving the security environment in the South Asian Sub-continent and towards world peace?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) and (b) On June 3, 1998, President Clinton stated that the United States and Russia are in the process of reducing their strategic nuclear arsenals by two-thirds, from the levels existing during the height of the Cold War, under the US-Russia "Treaty on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms" (START Treaties). President Clinton also briefly highlighted the various non-proliferation steps, such as the indefinite extension of the NPT and the signing of the CTBT. Under the 1993 START II Treaty, the United States and Russia will cut own their deployed startegic nuclear warheads to 3000—3500 each. These reduction are to be carried out by January 1, 2003 AD. However, at the global level, there is no evidence as yet on the part of the nuclear weapon states to take decisive and irreversible steps in reducing their reliance on nuclear weapons and moving towards a nuclear-weapon-free-world.

(c) India enjoys a consistent record as a responsible member of the international community and a pioneer and leading participant in the movement towards global nuclear disarmament At the global level, India has, individually and collectively with other like minded countries, put forward a number of intiatives intended to move the process forward including an Action Plan for creating a nuclear-weapons-free-world. More recently, India has welcomed the Joint Declaration, issued on June 9, 1998, by the Foreign Ministers of eight countries entitled "Towards a Nuclear-weapons-free-world. The Need for New Agenda". India has declared its readiness to cooperate closely with this initiative aimed at establishing a nuclear-weapon-weapon-free world in the coming millennium and the establishment of an equitable, non-discriminatory, non-violent and lasting international security order. With the objective of reducing tensions in